**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 714**

**सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को उत्‍त्‍ार देने हेतु**

**सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रभाव**

714. **श्री प्यारीमोहन महापात्रः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न चरणों में विद्युत की लागत की दृष्टि से परिकल्पित एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का क्या प्रभाव होगा;

(ख) क्या भारत ऐसे सभी स्तरों पर चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में बना रहेगा; और

(ग) प्रधानमंत्री का ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम अपेक्षाकृत ऊंची विद्युत लागत द्वारा किस हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा?

**उत्‍त्‍ार**

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सौर पीवी हेतु एक जेनेरिक स्तरीकृत उत्पादन शुल्क 7.04 रुपए/किलोवाट घंटा (त्वरित मूल्यह्रास के बिना) और 6.35 रुपए/किलोवाट घंटा (त्वरित मूल्यह्रास के साथ) का निर्धारण किया है। सौर विद्युत की लागत राज्य और केंद्रीय सरकार के संगठनों द्वारा विभिन्न निविदाओं में कम होती नजर आ रही है। यदि, नए और भविष्य में लगाए जाने वाले संयंत्रों में ताप विद्युत की लागत से उसकी तुलना की जाए, तो अन्तर बहुत ही कम है जिसके ताप की लागत बढ़ने पर और भी कम होने का अनुमान है। आगामी वर्षों में नए ताप विद्युत की तुलना में सौर विद्युत के अधिक सस्ता होने की संभावना है। अतः दीर्घ अवधि में विद्युत लागत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. चूंकि भारतीय विनिर्माण को प्रतियोगितात्मक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं इसलिए बाजार की स्थिति लगातार बदल रही है।
3. क्षमता को बढ़ाने से विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आएगी और इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सौर क्षमता लक्ष्य की दीर्घावधि व्यवहार्यता देश में सौर विनिर्माण सुविधाओं की संस्थापना में अभिप्रेरक के रूप में कार्य करेगी।